उपसभापति : मंत्री जी, आप खाली बिहार का दे रहे हैं । What about Andhra ? What about Karnataka and Maharashtra ? It is discrimination against other States.

श्री रामेश्वर ठाकुर : ये आंकड़े मैं मध्य प्रदेश के दे रहा हूं ।

उपसभापति : फिर आप बाद में बोल दीजिएगा । अभी लंच हो जाएगा ...**(व्यवधान)**.....

What about Karnataka, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Maharashtra ?

SHRI SARADA MOHANTY : And what about Orissa, Madam ?...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN : It is only about Bihar. .....*(Interruptions)*... I would request the Hon. Minister to give completely all the figures for all the States so that the States which have got a drought would have an idea of what is happening for their States. I know you are from Bihar. You have got better information about it. The House is adjourned for lunch till 2.30 P. M.

The House then adjourned for lunch at thirty two minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-three minutes past two of the clock, **The Vice-Chairman Shri MD. Salim** in the Chair.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Prevailing drought conditions in different parts of the country—Contd.

चौधरी हरि सिंह (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, इस देश की एक बड़ी विडंबना है कि देश के बहुत बड़े हिस्से, पूर्व, उत्तर और पश्चिम, सब तरफ बाढ़ का प्रकोप रहा । पिछले दिनों में इसी सदन में बाढ़ के ऊपर बड़ी गंभीरतापूर्वक चर्चा की । लेकिन यह भी विडंबना है कि आज देश के बहुत से राज्यों के अनेक जिलों में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है । अभी मंत्री जी ने अपने बयान में बताया कि अनेक स्टेट्स में सूखा पड़ा हुआ है, जिसमें बिहार भी है, कर्नाटक भी है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है । लेकिन मैं मंत्री जी का ध्यान विशेषतौर से उत्तर प्रदेश की तरफ दिलाना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में उत्तर प्रदेश का जिक्र तो किया है लेकिन बहुत थोड़ा-सा किया है । मालूम पड़ता है कि अधिकारी-वर्ग ने माननीय मंत्री जी को उत्तर प्रदेश के सारे जिलों की पूरी रिपोर्ट—जो सारे जिलों की स्थिति है उनकी सूखे के संबंध में पूरी रिपोर्ट आन दि स्पाट जाकर नहीं दी है । मेरे ख्याल से ऐसा इसलिये हुआ क्योंकि वहां पर राज्यपाल महोदय का शासन है और अधिकारी वर्ग को इसमें जो दिलचस्पी लेनी चाहिये थी, उसने यह दिलचस्पी नहीं ली । मान्यवर, मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के 42 जिलों की अनेक तहसिलों में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है । इलाहाबाद का माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया है लेकिन उसके अलावा आजमगढ़ है, बनारस है, मऊ है, मिर्जापुर है । ये सब जिले भयंकर सूखे की चपेट में हैं । वहां पर आदमियों को पीने के लिये पानी नहीं मिल पा रहा है, भोजन नहीं मिल पा रहा है । साथ ही साथ वहां जो पशु हैं उनको चारा नहीं मिल पा रहा है । यह स्थिति जो है यह उत्तर प्रदेश की है । लगता है कि कहीं कम्युनिकेशन गैप है जिसके कारण उत्तर प्रदेश में जो सूखे की स्थिति है उसकी सही जानकारी केंद्रीय सरकार को नहीं मिल पायी है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सूखे की जो स्थिति उत्तर प्रदेश की है वह उसकी जानकारी सदन को दे दें । जैसा कहा गया कि वहां पर भयंकर सूखा है वैसे ही यह भी सही है और जैसा आप देखते हैं कि प्रकृति का एक नियम है कि हर तीसरे साल देश में सूखा पड़ता है । जैसे सूखा टलता नहीं है वैसे ही बाढ़ का प्रकोप भी भयंकर रहता है । यह प्रकृति का नियम है कि सूखा भी पड़ता है और हर साल बाढ़ भी आती है । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह जो परमानेंट फीचर है, बाढ़ और सूखा, इसके लिये बाकायदा वार फुटिंग पर हमको काम करना चाहिये । हमको यह तय कर लेना चाहिये कि कौन-सी स्टेट में, कौन से जिलों के किन हिस्सों में, किन इलाकों में सूखा पड़ता है, वहां पर इमीडिपेटली रिलीफ का काम किस तरह से हो सकता है । दूरदराज इलाकों में जो काम पहले से करना चाहिये उसे कर दिया जाना चाहिये । होता यह है कि जब सूखा पड़ता है तो फिर दौड़ते हैं । मुझे खुशी है कि हमारे मंत्री जी ने अपने बयान में बताया कि बहुत सारा रुपया दिया गया । उसे 180 करोड़ रुपया मिला और बिहार को तो 330 करोड़ रुपया मिला । अभी माननीय ठाकुर साहब ने बताया कि बिहार को इतने सारे रुपये दिये गये । तो मुझे लगता है कि केंद्रीय सरकार इस मायने में बड़ी जागरूक, चेतन रही । इस समस्या का उसको आभास था इसलिये फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं हुई । प्रधानमंत्री जी ने खुद सूखा पीड़ित इलाकों का दौरा किया, बाढ़ पीड़ित इलाकों का भी उन्होंने दौरा किया । हमारे कृषि मंत्री जी ने भी दौरा किया । तो केंद्र सरकार का यह रोल नहीं रहा है कि वह प्राकृतिक मर्सी पर लोगों को छोड़कर बैठी रही । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बाढ़ और सूखा होने के बावजूद भूख के कारण लोगों की जान जो प्राय: बड़े पैमाने पर जाती है, वह नहीं हो पाया । हमारी मिलेट्री के नौजवानों ने बाढ़ में काम किया, सेना के लोगों ने काम किया, पुलिसवालों ने काम किया है, वालेंटरी आर्गनाइजेशन ने काम किया । इस बार जो भयंकर बाढ़ आयी, सरकार की सूझबूझ, दूरदर्शी का नतीजा है कि इससे जितना नुकसान होना चाहिये था, जितना नुकसान हमें लग रहा था, वह नहीं हुआ, बहुत कम नुकसान हुआ । इसके लिये हमारी केंद्र की सरकार बधाई की पात्र है जो उसने इस सारी बिगड़ती अवस्था को, इस भयंकर

आपदा और विपदा को अपने कामों से समेट लिया । जैसा मैंने कहा जहां सूखा था वहां पर सूखा राहत काम किया । मैं कहना चाहता हूं कि जिन इलाकों में पानी कम बरसता है, जहां पर बरसात कभी-कभी होती है, उन इलाकों में नयी नयी योजनाओं के द्वारा, नयी नयी प्लानिंग से नहरें बनायी जांय, वहां पर गहरे ट्यूबवेल खुदवाये जांय । साथ ही इन इलाकों के किसानों को स्पेशल, विशेष धनराशि देकर उनके लिये प्राइवेट ट्यूबवेल बनाये जांय । यह जो सूखे की स्थिति भयंकर हो गयी है उसका नतीजा यह है कि बिजली जो मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पाती । बिजली की व्यवस्था खराब है, वह अप्रयोराइड की बात छोड़ दीजिये, मिनिमम भी नहीं मिल पा रही है । इसके कारण किसान की फसल नष्ट हो गयी है, सूख गयी है और किसान अपने घर में जाकर निराश होकर बैठा हुआ है कि हमको एक पैसा मिलने वाला नहीं है । खेतों के ऊपर खाद का, बीज का, को-आपरेटिव का, किन्हीं दूसरी संस्थाओं का उसके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, उसको इनकी किस्तें देनी हैं । इस कारण वह बेचारा परेशान है । मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि बाढ़ के लिये तो आप कर ही दें और सूखे के जो इलाके हैं, जहां पर किसानों की फसल जलकर चौपट हो गयी है, नष्ट हो गयी है, तो उन किसानों का जो कर्जा है उसकी कम से कम पार्शियल धनराशि माफ कर दी जाय, उनका सूद माफ कर दिया जाय । जिस फसल के सहारे वह अपनी किस्त दे सकते थे । कम से कम जितनी किस्त उनकी कर्ज की है, को-आपरेटिव की है या और जिन संस्थाओं का जो रुपया उनको इस फसल से देना था, जो जलकर राख हो गयी है, उतनी धनराशि उनकी जरूर माफ कर देनी चाहिये । जैसा मैंने कहा कि परमानेंट नेचर के काम जो इस सूखे से प्रभावित एरिया के लिये इंगित हैं उनको वहां पर जैसे मैंने कहा नहर बनाना, ट्यूबवेल बनाना और इसके साथ-साथ जैसे मैंने कहा कि उन इलाकों में जिस तरीके के बीज और फसलों की जरूरत है उसी तरह के एक्सपेरीमेंट कर के वहां पर खेती कराया जाना बहुत जरूरी है । जब सूखा पड़ता है तो राहत के लिए बहुत-सा रुपया दिया जाता है । जैसे कि मैं अक्सर देखता रहता हूं, होता यह है कि इसमें सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ जो हमारे लोकल वर्कर हैं, सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कहता, जागरूक नागरिक भी हैं, जो संस्थाएं सेवारत हैं, पोलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, इन सब का इनवाल्वमेंट होना चाहिये । देखा यह गया है कि अगर सूखे या बाढ़ के नुकसान का जायज़ा लेना होता है तो जो पटवारी लिख कर दे देता है वही मान लिया जाता है । अगर किसी ने पटवारी को पैसा दे दिया तो उसके नुकसान का अधिक जायज़ा भेज दिया जाता है । यदि कोई किसान या मजदूर पैसा नहीं दे सकता तो उसका नुकसान का जायज़ा कम चला जाता है । इसलिए मेरा कहना यह है कि किसान की किस्मत का फैसला, नफे-नुक्सान का फैसला पटवारी के भरोसे पर आप मत छोड़िये । इस काम में ऐसी कोई एजेंसी इनवाल्व हो जो वालेंटरी आर्गेनाइज़ेशन हो जो सही जायज़ा दे सके । उसकी भरपाई न हो तो कम से कम किसानों को, मजदूरों को दूसरे आर्थिक संकट से बचा सकें । इसके साथ-साथ जब सूखा पड़ता है तो किसान पर और भी मुसीबत आ जाती है । किसान की जिन्दगी से जुड़ा हुआ मजदूर भी होता है । ऐसे संकट के समय पशु भूखे मरते हैं क्योंकि फॉडर उनको नहीं मिल पाता है । जो इस तरह के क्षेत्र हैं उन राज्यों में जो खेतिहर मजदूर होते हैं वह सब से पूअर-पेट होते हैं जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं है । उनकी तो और भी दुर्गति हो जाती है । सूखे की स्थिति में न तो किसान काम करा पाता है और न उनके पास पैसा होता है जिससे वह मजदूर अकाल से पीड़ित हो जाते हैं । उनको घर-बार छोड़ने की नौबत आ जाती है । माननीय मंत्री जी से मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे एरियाज़ में जो हमारे विकास के काम हैं जैसे जवाहर रोजगार योजना है, इस के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर काम करवाने चाहिये जिससे मजदूरों और किसानों को काम मिल सके । यह मेरा आपसे आग्रह है । उपसभाध्यक्ष महोदय, सूखा पड़ता क्यों है ? इसके प्राकृतिक कारण भी हैं जैसे पेड़ों का लगाया जाना । हम यह देखते हैं कि हर साल पेड़ तो लगाए जाते हैं लेकिन उनका लालन-पालन नहीं होता है, पानी देते नहीं हैं, देखभाल करते नहीं हैं । करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है । सरकारी मशीनरी एक दफा पेड़-पौधे लगाने के बाद संख्या दे देती है । आंकड़े अखबारों में निकलने चाहियें, कभी-कभी पौधा लगाते हुए हमारी किसी की फोटो भी छप जाती है लेकिन उसका रख-रखाव नहीं होता है जिससे सब बेकार चला जाता है । इन सब चीजों को प्रेक्टीकल शेप दी जानी चाहिये । मुझे विदेश जाने का मौका मिला । वहां मैंने देखा कि पेड़ों की जड़ों के अन्दर ह्यूम पाइप लगे हुए हैं जो बाकायदा जड़ों में फिट रहते हैं । जो पेड़-पौधे सड़कों के किनारे होते हैं उन पर लोहे का जाल सा बना दिया जाता है इससे वहां से गुज़रने वाले वाहनों से उनको कोई नुकसान नहीं हो सकता है । यह सारे सिस्टम हिन्दुस्तान में होना आवश्यक है । अगर हमको पोल्यूशन से, बाढ़ से और सूखे से बचना है तो हमारी जो नयी नयी टेक्नीक्स हैं, उनको प्रेक्टीकल रूप में लाना होगा, तभी हम सूखे से बच सकते हैं । मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, पुन: यह कहना चाहता हूं कि भारत का किसान तो बड़ा गरीब आदमी है । मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि बिजली वालों से सख्त हंटर से काम लें, ऐसा लगता है कि जैसे बिजली वालों पर किसी की हकूमत नहीं चलती । जब सूखा पड़ता है तो बिजली वाले और भी चैन से बैठ जाते हैं । जब तक बिजली और किसान का ताल्लुक सीधा-सीधा नहीं होगा, पानी नहीं मिलेगा । आजकल हमारा पानी का स्तर भी बहुत नीचे चला गया है । हमारे ट्यूबवेल इसके कारण बेकार हो गये हैं । उनको पुन: नया रूप देने की आवश्यकता है, नयी स्कीमें प्रारंभ कर के नये ऋण देने की आवश्यकता है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि नये परिप्रेक्ष्य में सारे देश के अन्दर, सारे राज्यों के अन्दर जहां अक्सर सूखा पड़ता रहता है, उनके लिए कोई विशेष योजना बना कर उनको इस संकट से उबारिये । इन्हीं अल्फाज़ के साथ मैं फिर आपको धन्यवाद देता हूं कि इस महकमे के अन्दर आपने दोनों पर कड़ी नज़र रख कर देश को भारी क्षति से बचाया है । धन्यवाद ।

श्री अनन्त राम जायसवाल (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इससे पहले इसी सभा में अतिवृष्टि और बाढ़ पर चर्चा हो चुकी है । उसमें हिस्सा लेते हुए मैंने निवेदन किया था कि बाढ़ और सूखा अपने देश में हर साल की घटना है । और उस बात को मैं फिर आज दोहराना चाहता हूं । इस साल एक साथ बाढ़ भी है और सूखा भी है । देश के कुछ इलाके बाढ़ से तबाह और कुछ सूखा या अकाल में फंसे हुए है ।

इसमें सब से बड़े दुख की बात यह है कि समय से चेता नहीं जाता, कार्यवाही नहीं की जाती । बिहार के जिले ले लीजिए आप, पलामू है, गरवा है, चित्रा है । पिछले अक्तूबर में ही मालूम हो गया था कि आगे क्या होने वाला है । खरीफ की फसल नष्ट हो चुकी थी, रबी भी ठीक हुई नहीं । संकेत साफ था कि आगे भयंकर सूखा और अकाल की हालत बिहार में जोर के साथ आ रही है ।

जहां तक उड़ीसा का सवाल है, तो उड़ीसा में भी कालाहांडी का किस्सा मालूम नहीं कब से छप रहा है । मुस्तकिल सूखा वहां पर है और उसी के साथ मध्य प्रदेश का इलाका मिला हुआ है । अब की दफा कर्नाटक भी और तमिल नाडु का भी एक जिला, गुजरात का इलाका और अंत में उत्तर प्रदेश के इलाके में मैं खुद देख कर आया हूं कि बहुत जगह तो धन अभी बोया नहीं जा सका पानी की कमी की वजह से और जहां बोया गया है, वह भी सूख रहा है पानी की कमी की वजह से ।

तो यह स्थिति अपने देश में है और इसमें और ज्यादा जाइये कि जहां पर यह हालत होती है, वहां पर पानी की कमी, खाने की कमी, काम की कमी, जानवरों के चारे की कमी—यह चीजें भी इसके साथ आती है ।

उपसभापतिजी, यह कोई कविता नहीं है, वास्तविकता है कि पलामू वगैरह के लोग पेड़ों की पत्तियां और जड़े खाते रहे हैं । खाना नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है तो लोग भूख से मरते हैं । चाहे केन्द्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, इनकी जबान पर चढ़ गया है कि किसी को भूख से मरने नहीं देंगे । लेकिन हर साल लोग मरते हैं । इस दफा भी इन इलाकों में भूख से मौतों का समाचार छप रहा है । उड़ीसा से भी भूख मौतों की खबर आई, बिहार से भी भूख मौतों की खबर आई और मद्रास से भी आई । यह आन्ध्र प्रदेश जो माननीय प्रधान मंत्री जी का अपना प्रदेश है, वहां से भी खबरें आई हैं । तो इस तरह से खबरें आती हैं । तो मैं आज इस सभा में बहुत ही नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर जो यह भूख लगातार रहती है—यह सही है कि भूख से एक दिन में आदमी नहीं मरता है लेकिन धीरे-धीरे करके, थोड़ा-थोड़ा करके आदमी बराबर मरता रहता है और एक दिन वह सचमुच मर जाता है । लेकिन सरकार ऐसी मौतों को बता देती है कि यह किसी बीमारी की वजह से हो गई । जो भूख के ही कारण बीमारियां हैं, चाहे तपेदिक की हो या और कोई बीमारी हो, यह भूख की वजह से है । इनसे जब आदमी मर जाते है, तो कह देते है कि यह तो नैसर्गिक मौत है । इससे पहले भी मैं इस सभा में मांग कर चुका हूं कि कोई एक्सपर्ट कमेटी बनवा दीजिए आप, जो तय करे कि यह भूख की मौत है या नहीं है । आखिर लम्बे अरसे तक लोगों को कम खाना मिलेगा, मालन्युट्रीशन रहेगा, तो मौत के अलावा और उनका क्या हाल होगा । बीमारी उनको पकड़ेगी और वह उससे मरेंगे । तो इस तथ्य को सरकार को कबूल कर लेना चाहिए । अगर एक दफा सरकार कबूल कर लेती है, तो फिर उसका उपाय भी करने को सरकार मजबूर होगी । लेकिन क्योंकि सरकार इन को कबूलती नहीं है, इसलिए सरकार के काम पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है ।

मेरा पहला निवेदन है और मैं जानना चाहूंगा कि मंत्री महोदय जब उत्तर देंगे आज की इस बहस का तो क्या उसमें वे इस प्रश्न पर ध्यान रखेंगे ? मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न पर ध्यान रखा जाए और जो मौतें हुई है अन्न की वजह से और खाने की कमी से, तो उसको सरकार को स्वीकार करना चाहिए ।

सरकार डरती होगी कि इससे अपने देश में और विदशों में उसकी बड़ी बदनामी होगी, लेकिन वह बदनामी तो होती ही है । आप लाख छिपायें, लेकिन चीजें छिपती नहीं है । क्या भूख से बने कंकाल बच्चों की तस्वीरें अखबारों में नहीं छपी हैं ? यह तस्वीरें तो छपी ही हैं, जिस चीज़ को आप छिपाना चाहते हैं वह तो होती ही है । क्या यह बात अखबारों में नहीं छपी अपने देश के और बाहर के अखबारों में और मीडिया में क्या यह बात नहीं आई है कि भूख के कारण माताओं और पिताओं को अपने बच्चों को बीस-बीस रुपये में बेचना पड़ा है । यह चीजें तो छप रही हैं इसलिए एक दफा आप अगर कबूल कर लेंगे तो शायद ईमानदारी से इसका हल खोजने की कोशिश की जाएगी । आज सरकार इस मसले की तरफ ध्यान नहीं देती है । मामला बहुत ही पेथेटिक है । यह सभा 26 जुलाई से शुरू होने वाली थी, 27 को लोक सभा में और 30 को इसी सभा में इस प्रश्न पर सवाल उठा । माननीय मंत्री जी शायद आप ही ने जबाब दिया होगा ।

सवाल था कि आज के दिन या वर्तमान में देश के किन-किन जिलों में सूखा है और जवाब आता है कि सूचना एकत्र की जा रही है । मामला शुरू हो गया था पिछले अक्तूबर में, मार्च में, फिर यह सैशन आ रहा था और यह सवाल पूछा जाएगा यह तो सब को मालूम था लेकिन जवाब मिलता है कि सूचना एकत्र की जा रही है मालूम नहीं है कि वह सूचना एकत्र हुई है या नहीं ? इस सत्र के रहते वह सूचना एकत्र हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ? यह है इनडिफ्रेंस, मतलब कल्पेबल इनडिफ्रेंस जिसका चार्ज सरकार के ऊपर जाता है । अगर आपके पास यह जानकारी आ गई हो तो क्या कृपा करके वह जानकारी आज आप सदन में रखेंगे ? एक इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि जब यह मुसीबत आती है बाढ़ या सूखा की तो जो इससे प्रभावित लोग होते है उनके लिए तो मुसीबत है, लेकिन जो सरकारी अमला है उसके लिए यह मुसीबत वरदान बन कर आती है । वे चाहते हैं कि हर साल यह मामला रहे । इसका मुस्तकिल हल इसलिए नहीं निकाला जाता कि माननीय मंत्री जी कि यह जो कर्ताधर्ता आपके सरकारी आफिसर है, कलैक्टर है, कमिशनर है, एस० डी० एम० तहसीलदार वगैरह लेखपाल तक यह सिलसिला जाता

है, ये सब उससे फायदा उठाते हैं । राहत के लिए जो मदद लोगों के लिए जाती है, वह उनके पास न जा कर इन लोगों की जेबों तक पहुंच जाती है । नतीजा यह होता है कि ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि इसका हल मुस्तकिल निकले, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए । सरकारी आफिसर एक तरह से सोच सकते हैं, क्योंकि उनका जनता से कोई ज्यादा लेना-देना नहीं रहता, लेकिन सरकार को तो सोचना ही चाहिए । जनप्रतिनिधि होकर हम यहां पर आते हैं तो यह चीजें हर साल हों और होती ही रहें, सरकार इसको होने ही दे और उसका मुस्तकिल हल न सोचा जाए तो माननीय मंत्री जी सदन को प्रसन्नता होगी अगर आप इस चीज़ को बतायेंगे कि इस सूखा वगैरह से निपटने के लिए मुस्तकिल क्या-क्या उपाय सरकार कर रही है ?

चौथी चीज़ यह है कि जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि वहां पर काम की जरूरत है, अन्न की जरूरत है और पानी की जरूरत है, तो इसके लिए तुरन्त सरकार क्या कर रही है ? एक चीज़ याद रखिएगा । कभी-कभी सरकार एक काम हाथ में लेती है और उसे बीच में ही रोक देती है । उसके और खतरनाक नतीजे होते हैं । माननीय मंत्री मैं यह कहना चाहता हूं और पूरे जोर से कहना चाहता हूं कि आदमी की जान से बढ़ कर कोई चीज़ नहीं है, उसी के लिए सारी कार्यवाही है । सरकार हिसाब लगाए कि इन भूखे लोगों के लिए अगर लंगर चला दें, दो जून आप खाना न दें, एक ही जून उनको दे और वह भी बहुत कुछ नहीं सिर्फ कुछ रोटी और दाल वगैरह ही दें, जहां-जहां पर ये हलाके हैं उनके लिए लंगर चलाएं और जब तक अगली फसल न आ जाए तब तक यह चलना चाहिए, क्या इस पर सरकार ध्यान देगी ? ये कुछ चीजें ऐसी हैं, मान्यवर, जो हर दफा होती हैं और हर दफा दोहराई जाती हैं लेकिन उनका कोई नतीजा निकलता नहीं है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा, लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं और मैं भी आपका एक तरह से प्रशंसक ही हूं, लेकिन उससे क्या यह चीज़ जो है आपके बोलने में जो असर पैदा होता है वह काम में दिखना चाहिए, यही मेरा आपसे निवेदन है । धन्यवाद ।

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO (Andhra Pradesh) : Mr. Vice-Chairman, I am glad that we are discussing this serious issue now in the midst of so many non-issues cropping up all of a sudden and taking away the time of the House.

I have carefully gone through the statement made by the hon. Minister in which he has only stated certain facts and offered no solution to the problem. As it is, he has been expressing so much of concern for the agriculturists and it is good. At the same time I must say that the agrarian community has been greatly distressed for want of remunerative prices for their produce. Last year, they had to sell their produce at very low prices. Adding to their sufferings, this drought has caused a great damage and we have to take a serious note of it.

It is true that every year we face some problem or the other. Even this year, floods are affecting so many States like Punjab, Bengal, Tripura, Assam and so many other parts of the country. At the same time, this drought has been there for a prolonged period in many areas of various States. Last time also we discussed this subject and I was one of those who participated in the discussion. Then also the distressing situation of Kalahandi was brought to the notice of the hon. Minister and his attention was drawn to the situation in Bihar and Madhya Pradesh in particular. But those affected areas continue to face the same problem. What steps have been taken and how far have we been able to provide relief to the people ? How far have we been able to solve the problem ? Obviously, not much could be done since those areas still continue to suffer in the same manner as they suffered before. So, this prolonged drought is affecting so many States and Andhra Pradesh in particular. As the hon. Minister himself has said, Andhra Pradesh is facing a severe drought condition. It is one of the worst-affected State so far as this present drought is concerned. Even the Chief Minister said that this is unprecedented. How far is the Government—either the State Government or the Central Government—alert to apply its mind to find a solution to the problem ? Last time itself, as I said earlier, I mentioned about the drought condition and how it is going to pose a serious danger in the rural areas in particular, and the situation remains the same. Now the State Government has woken up in April and by May end, the Central team also visited our State and assessed the situation. We had expected some immediate help. But from May-end to July-end, nothing concrete had come about. Only promises had been there. Representations had been there. After the assessment by the Central team, the State Government had requested that at least Rs. 645 crores must come from the Centre by way of aid. As my friend, Mr. Jaipal Reddy, was saying, only Rs. 29 crores had been given to the State and Rs. 127 crores is promised. That too, they had to collect from various departments which have been, perhaps, wanting these funds for other purposes.

The situation is very serious in the sense that people are simply driving their cattle and sheep to the slaughter-house. People are migrating to other areas. The other day—2nd August—I was in Mahbubnagar. On the route from Hyderabad to Mahbubnagar, I came across hundread of cattle and sheep being taken to the slaughter-house. The farmers are being com-

pelled to sell away whatever cattle they are having.

SHRI V. GOPALSAMY: They are taking the cattle to Kerala.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: The situation is very serious. From Mahbubnagar alone, 6 lakh people have migrated so far. Up to last week, there was no rain at all. A little bit of rainfall was there, but I found that the ponds and tanks were all dry. Not a drop of water could be seen, in spite of the little drizzle sometimes. This is no relief to the people at all. I do not think this little bit of rainfall would help in improving the famine situation. The situation is deteriorating. The State Government is not able to render substantial help. Of course, they were supplying some fodder. In Mahbubnagar District itself, some lorry-loads of fodder was supplied at the rate of 4 or 5 lorry-loads per mandal which would be having about 25 villages. You can imagine how meagre it is. They have also dug some borewells. However, the water table has gone down so low—it has gone down as much as 500 ft. below the surface—that the borewells could not be of much help to the people in solving their drinking water problem. The people are undergoing a lot of suffering. Up till now, except for the State Government attending to these two tasks, i. e. supplying this meager quantity of fodder and digging borewells here and there, nothing much had been done. Eleven districts are affected by drought; 7 districts are seriously affected and 4 districts are partially affected. This is the kind of situation faced by the Andhra Pradesh Government.

Under these conditions, how can the State Government give adequate relief? Up till now, not even a kg. of rice has been given free to any suffering human being. Rice is not supplied even at the reduced rate of Rs. 2 per kg. Further, the farmers are given no credit facilities so that they can, somehow, tackle their problems and get over the crisis. So, if this is the State of affairs in Andhra Pradesh, perhaps the same situation may be there in other States also because so many other friends have spoken about it, particularly from Madhya Pradesh, Bihar and so many other States. That is why I say that the Central Government has not applied its mind seriously to this problem either in the past or at the present time. If they had applied their mind seriously, the hon. Minister should have come out with certain new measures. Perhaps he would come out while replying to the Calling Attention because he has asked us to remain here and we hope he will spell out certain measures which would give relief to the people living in the famine-stricken areas.

Sir, the loss value of the crops in Andhra Pradesh is to the tune of Rs. 550 crores or so as compared to 1991-92. As they have put it, 15 lakhs agricultural labourers, poor peasants and others are suffering for want of employment opportunities. Also employment opportunities are lost. The loss of minimum wage was officially assessed at Rs. 255 crores. So, these things are happening. It is of no use saying that Jawahar Rozgar Yojna Fund is there and it would be giving a lot of relief to the famine-stricken areas. That fund is not meant for famine-stricken areas, it is meant for application in normal conditions. So, the hon. Minister has to take it seriously and think of taking serious steps.

So many solutions are offered, but I am surprised to know that in Mahboobnagar even the old age pension for elders is not being given by the State Government for the last 4 months. The youngsters have already left the villages. Only the old people are remaining there. Their pension is also not being sent. How can they bear all this? Permanent relief measures have not been taken up at all in drought-prone areas. For instance, in Mehboobnagar district Jurala project should have been completed by now, but it has not been completed. Medium-scale projects also have been pending for years together.

Even the twin cities of Hyderabad and Secunderabad are hit by water scarcity problem. The water supplied to both the cities now is only half the quantity of what is required by the population of these cities. There is no plan. Prior to this period there had been plans but the Government did not take action and now the people are suffering for want of even drinking water. This is the situation that is developing there.

My colleague, Shri Jaipal Reddy, has suggested that a Parliamentarty delegation should visit the seriously drought-affected areas, but I do not know what such a delegation would do. I am not against any delegation going there, but only if the Government is prepared to take their recommendations seriously and implement them—only if they have got such a mind—going of such a Parliamentary delegation there would be of help and not otherwise. If they depend on the routine schemes and routine methods, no immediate benefit would be there.

So, compensation for farmers, sale of rice at a lower price, say, at Rs. 2 a kilo, at least in the affected areas, and other credit facilities for the farmers should be arranged immediately. The Central Government should see that the State Government are given whatever is asked for, or whatever is sanctioned for them, immediately. Otherwise it would be of no help at all. They would go on pleading that the Central Government has not given them any help till now and so they have not been able to do anything. This would be the routine explanation and it would be of no use. So, whatever help is sought for must be immediately given, and immediately giving this help would also hasten the process of the State Government attending to the famine-affected areas very seriously.

I hope our Agriculture Minister would take these things seriously and attend to them. He is concerned, I do appreciate it, but what has been the result and what would be the result if the same old way is followed even now? That is why he should come forward with certain measures which would give real relief to the affected people immediately.

Thank you.

श्री कामेश्वर पासवान (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी का वक्तव्य सुन रहा था । इसके पहले भी उन्होंने बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर अपना वक्तव्य दिया था । उपसभाध्यक्ष, महोदय, दोनों में मुझे कुछ साम्य नजर आता है । जहां तक बिहार का सवाल है, वहां बाढ़ के सम्बन्ध में जो मौत की सूचना थी, उस दिन भी कृषि मंत्री के पास उपलब्ध नहीं थी और सुखाड़ का जो वक्तव्य आया है तथा बिहार से जो इनके पास प्रतिवेदन आया है उसमें भी बिहार के चार जिले हैं, जो अत्यधिक प्रभावित हैं । एक कमेटी ने वहां जाकर जांच की है । उसकी रिपोर्ट है कि लगभग 100 व्यक्ति भूख-जनित मौत के शिकार हुए हैं और बिहार सरकार से जो रिपोर्ट आई है, माननीय कृषि मंत्री के इस वक्तव्य में उसकी चर्चा तक नहीं है । मेरा निवेदन होगा कि माननीय कृषि मंत्री इसको सुधार लेंगे और आवश्यक समझें तो बिहार सरकार से पुन: एक बार इसकी जांच-पड़ताल करके प्रतिवेदन मांग लेंगे ।

महोदय, बिहार में पिछले तीन वर्षों से सुखाड़ का ताण्डव नृत्य हो रहा है । मुझे आश्चर्य है कि इससे पहले भी जब बिहार में सुखाड़ था, तो न केन्द्र सरकार ने और न बिहार सरकार ने ही उस पर किसी तरह की चिन्ता की थी । आज जब बिहार के बाढ़ सुखाड़ पर चर्चा हो रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले वर्षों बिहार में जो सुखाड़ था, उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है । आज बिहार की स्थिति यह है कि वहां के 90 प्रतिशत जो ट्यूबवेल हैं, वह कार्यरत नहीं हैं, बेकार पड़े हुए हैं । पैसे के अभाव में उसकी मरम्मत भी नहीं हो रही है या सरकार इतनी संवेदनशून्य है कि जहां बिहार सरकार चरवाहा विद्यालय और पहलवान विद्यालयों पर पैसे व्यय कर रही है वहां पर जिस आदमी को भूख से बचाया जा सकता है उस पर सरकार का ध्यान नहीं गया है । वहां पर कैसे आदमी को भूख से बचाया जा सकता है, इस पर सरकार का ध्यान नहीं गया है और आश्चर्य यह है कि केन्द्रीय सरकार भी उस पर ध्यान नहीं दे रही है । वहां पर बिजली की बड़ी कमी है । वहां पर न्यूनतम आवश्यकता 1500 मेगावाट की है परंतु बिहार अपनी क्षमता के अनुसार 300 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है और 300 मेगावाट बाहर से मंगाता है । इसके बावजूद न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है । सारे ट्रांसफार्मर्स बेकार पड़े है जिसके कारण जो ट्यूबवेल सिंचाई योग्य है, बिजली के अभाव में वह भी बंद पड़े हुए है । इसलिए मेरा निवेदन होगा कि माननीय मंत्री जी फिर से एक बार बिहार के संदर्भ में प्रतिवेदन मंगवा लें और तब वहां की समस्या का निदान करने में आपको सहायता मिलेगी ।

महोदय, यह कहा गया है कि पूर्वानुमान यह था कि वहां पर चर्चा कम होगी । मेरा निवेदन यह है कि बिहार में औसतन जो वर्षा प्रत्येक वर्ष होती थी, उसमें से मात्र 20 प्रतिशत वर्षा बिहार में हुई है और जिसके परिणामस्वरूप आज बिहार के 44 जिले सुखाड़ की चपेट में आ गए हैं । ये अलग बात है कि सरकार की रिपोर्ट में कहा गया है कि वहां पर भूख से किसी की मौत नहीं हुई है । महोदय, मेरे पास जो रिपोर्ट पड़ी हुई है, मैं कृषि मंत्री जी को देना चाहूंगा । यह अत्यंत विश्वसनीय रिपोर्ट है जिसमें मैंने एक सूची तैयार की है कि भूखजनित मौत के शिकार कितने लोग हुए है ।

महोदय, बिहार के जो गढ़वा, पलामू और चकरा जिले हैं, जहां पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, उनका वहां जब दौरा हुआ, उसके बाद से वहां रिलीफ कार्य बंद हो गया । तीस जून को बिहार सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि यह फैमिन कोड के विरुद्ध है, इसलिए 30 जून के बाद वहां पर रिलीफ नहीं चलाई जा सकती है । इसलिए रिलीफ का काम बंद हो गया । मैं माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ऐसी परिस्थिति में जब लोग भूख से मर रहे हैं तो फैमिन कोड का सहारा लेकर लोगों को मौत के मुंह में नहीं धकेला जाना चाहिए । इसको आप देख लीजिएगा । मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूं । सरकार के पास जो प्रतिवेदन आया है बिहार सरकार का, उसको मैं चुनौती देता हूं और मेरे पास जो रिपोर्ट है, इसकी आप अपनी किसी एजेंसी से जांच करा लीजिए । मैं आपको लिस्ट दूंगा कितने व्यक्तियों की मौत हुई है ।

जहां तक छोटा नागपुर का सवाल है, वह पहाड़ी इलाका है । वहां पर जल स्तर इतना नीचा है कि आज यदि आधुनिकतम साधनों से भी जल निकासी का काम किया जाए तो असंभव नहीं तो कम से कम मुश्किल अवश्य है । इसलिए मेरा सुझाव होगा कि छोटा नागपुर इलाके में आप एक विशेष योजना चलाइए, केन्द्रीय सरकार की योजना चलाइए और वहां बड़े-बड़े तालाबों का निर्माण करिए और जब वर्षा वहां पर हो तो उस वर्षा के पानी को रिस्टोर करके रखिए और वही पानी कृषि में भी आएगा और

पेयजल के रूप में भी काम आएगा । आज वहां के आदिवासी लोगों को 10-10 किलोमीटर दूर तक पानी लेने के लिए जाना पड़ता है । वे पानी की तलाश में दिन भर भटकते हैं, फिर भी पानी उपलब्ध नहीं होता है । इतनी भयानक स्थिति है । मुझे लगता है कि जितनी गंभीर स्थिति है, उस स्थिति की रिपोर्ट सरकार के पास नहीं है और केन्द्रीय सरकार ने भी इसकी जरूरत नहीं समझी है कि पलामू गढ़वा और चकरा जैसे इलाकों में स्वयं किसी एजेंसी को भेजकर स्थिति की जांच कराए । महोदय, आज वहां पर भूख से जो लोग मर रहे हैं, उसको देखकर मुझे बंगाल के उस दुर्भिक्ष की याद ताजा हो जाती है जिसमें एक मां ने अपने बच्चे को काटकर, उसके मांस को भूनकर अपने उदर की पूर्ति की । इस अवसर पर मुझे एक मिथक का भी स्मरण हो आता है । तपस्वी विश्वामित्र जब भूख से पीड़ित हुए तो एक चांडाल के घर में उन्होंने चोरी की और चोरी की तो कुत्ते का पका हुआ मांस खाया लेकिन आज पलामू की स्थिति उससे भी बदतर है । मेरे पास जो रिपोर्ट है, उसको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं ।

महोदय, दिनांक 23 जून, 1993 को विश्रामपुर थाने के अंतर्गत लोखला गांव के विजयपाल की पत्नी प्रभादेवी ने भूख से बिलखते 4 वर्षीय अपनी बेटी अनीता के साथ-साथ 2 वर्षीय पुत्र कमलेश पाल को तथा 2 माह के नवजात शिशु को काट दिया और स्वयं भी आग में जलकर सदा-सर्वदा के लिए भूख से छुटकारा पा लिया ।

महोदय, यह तो एक घटना है परंतु मेरे प्रतिवेदन में लगभग एक सौ मौतों की सूचना इकट्ठी की गई है और गांव-गांव में जाकर, घटनास्थल पर जाकर, उस गांव के लोगों से पूछकर, उसके परिवार के लोगों से पूछकर, यह रिपोर्ट तैयार की गई है कि वहां भूख से मौतें हो रही हैं ।

मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन होगा कि बिहार के संदर्भ में एक विशेष योजना बनाइए । आप जानते है कि बिहार को भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा जा सकता है—उत्तरी बिहार, मध्य बिहार, छोटा नागपुर और संथाल परगना । उत्तरी बिहार में जो बाढ़ आई है, वह बिहार में अतिवृष्टि के कारण नहीं आई है बल्कि नेपाल में वर्षा अधिक होने से बाढ़ आई है, उसके कारण उत्तरी बिहार की नदियों में बाढ़ आई है और विडंबना यह है कि उत्तरी बिहार के जिन 8 जिलों में बाढ़ आई है, उसके कुछ प्रखंडों में सुखाड़ है ।

महोदय, इसको कहीं धुप कहीं छाया की दृष्टि से देखा जा सकता है । मुझे स्मरण है कि तत्कालीन सिंचाई मंत्री श्री के. एल. राव ने भी इस तरह की योजना बनाई थी, जो कांग्रेस सरकार के सिंचाई मंत्री थे । उन्होंने कहा था कि बिहार के लिए आवश्यक होगा कि नेपाल सरकार से वार्ता करके इन नदियों में तटबंध का निर्माण किया जाए । आजादी से पहले लार्ड वीवेल ने इसी तरह की योजना बनाई थी परंतु आज तक केन्द्र में कांग्रेस की सरकारें रही कुछ वर्षों को छोड़कर और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार रही लेकिन इनके ही सरकार के मंत्रीयों ने इस योजना की ओर देखने की जहमत नहीं उठाई । इसलिए मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बिहार राज्य सुखाड़ की चपेट में है और इसके 44 जिले इस चपेट में आ गए हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार के संदर्भ में एक विशेष योजना केन्द्रीय सरकार बनाए क्योंकि वहां पर दो तरह की प्राकृतिक मार होती है—बाढ़ और सुखाड़ ।

मुझे लगता है कि केन्द्रीय सरकार की तरह प्रकृति भी बिहार से ज्यादा सपना है । एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ सुखाड़ है । इसलिए केन्द्रीय सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि एक विशेष योजना बिहार के संदर्भ में बनाए, खासकर उन इलाकों के लिए जिनमें आदिवासी लोग रहते हैं जैसे छोटा नागपुर और संथाल परगना । ये लोग पेड़ के पत्ते और घास खाकर गुजारा करते हैं और कभी-कभी जहरीले पदार्थों को खाकर मौत के शिकार हो जाते हैं । उन आदिवासियों को आप मौत से बचा लीजिए । आपकी सरकार के लिए यह पुण्य की बात होगी । धन्यवाद ।

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, हमारे देश का जो भौगोलिक क्षेत्र है वह 329.3 मिलियन हेक्टेयर है जिसमें क्राप वाला क्षेत्र 140 मिलियन हैक्टेयर है । 68 फीसदी भौगोलिक क्षेत्र में 1125 मिलिमीटर से कम वर्षा होती है । पूरे देश के क्षेत्र को 35 भागों में बांटें तो 8 क्षेत्रों में पानी की कमी बताई जाती है जो पिछले आंकड़े इस बात के सबूत हैं ।

प्रतिवर्ष हम लोग सूखे और बाढ़ पर चर्चा करते हैं । यह बहुत अफसोसजनक बात है । पिछले समय हम लोगों ने बाढ़ के संबंध में चर्चा की थी और आज हम लोग सूखे की स्थिति से निपटने के बारे में चर्चा कर रहे हैं । पिछले दिनों हमारे देश के बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में अत्याधिक सूखे की स्थिति निर्मित्त हुई । यदि हम मध्य प्रदेश को लें तो सन् 1992 में 15 जिले प्रभावित हुए जिसमें 9 जिलों में से 28 तहसील तो बुरी तरह प्रभावित हुए जिससे करीब 48 लाख लोग प्रभावित हुए थे । प्रधानमंत्री ने 17 अप्रैल, 1993 को मध्य प्रदेश का दौरा भी किया था और 100 करोड़ रुपये की रूरल डेवलमेंट मिनिस्ट्री के अन्तर्गत स्वीकृति कराई थी जिसमें 90 करोड़ जेआरवाई के तहत, 4 करोड़ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की एआरडब्लू (एसपी) के अन्तर्गत और 1 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष के अन्तर्गत और 5 करोड़ रुपये डिपार्टमेंट आफ वेस्ट लैंड के अन्तर्गत उन्होंने रुपये देने की घोषणा की थी । लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यद्यपि प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की पवित्र भूमि पर यह घोषणा की लेकिन 5 करोड़ जो डिपार्टमेंट आफ वेस्टलैंड के हैं वह अभी तक मध्य प्रदेश को नहीं मिल पाये हैं । निश्चितरूप से इस संबंध में मंत्री महोदय कुछ प्रयास करेंगे ऐसा मेरा अनुरोध है ।

यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार से अभी तक इस संबंध में कोई प्रोपोजल नहीं आया है लेकिन केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार से पहल तो कर ही सकती है, ऐसी कोशिश की

जानी चाहिए और मुझे विश्वास है । यह कोई मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं । लेकिन जो कृषि मंत्री जी हैं आदरणीय जाखड़ जी और भाई अरविन्द नेताम जिनकी युगल जोड़ी है इनके सामने जो युगल समस्या है बाढ़ और सूखे की इससे निपटने के लिए एक सार्थक भूमिका अदा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है ।

1993 के आकड़ों को यदि लें तो मध्य प्रदेश विशेषरूप से जो वेस्ट मध्य प्रदेश है उसमें 23 प्रतिशत बारिश की कमी हुई है जिससे लगभग 70 से 75 परसेंट वाला जो क्षेत्र है उसमें कम बारिश की वजह से वहां की पैदावार प्रभावित होगी और इससे निश्चितरूप से राज्य को काफी नुकसान होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है । जो कैलैमिटी रिलीफ फंड है उसके तहत मध्य प्रदेश के लिए एनुअल एलोकेशन है वह 37 करोड़ रुपये का है लेकिन अभी तक जो किश्तें मिली हैं उसके तहत केवल 20.81 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश को दिये गये हैं । मेरा अनुरोध है क्योंकि मध्य प्रदेश बुरे तरीके से सूखे से प्रभावित राज्य रहा है तो जितना एनुअल एलोकेशन है वह पूरा का पूरा आप स्वीकृत करने की कृपा करें ।

माननीय कृषि मंत्री श्री बलराम जाखड़ जी ने मध्य प्रदेश में दो दिन तक दौरा किया । उन्होंने खुद ही अपनी आंखों से देखा है कि मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष कितने जिले प्रभावित हुए थे और इस बार लगभग 17 जिले प्रभावित हुए हैं । आपने एक सेन्ट्रल टीम भी सरगुजा जिले में भेजी थीं जहां भूख से लोगों की मृत्यु हुई थी । इस सेन्ट्रल टीम ने अनुशंसा की थी कि ज्यादा से ज्यादा फंड जेआरवाई के तहत दिया जाए । साथी जी 4-5 सितम्बर, 93 को माननीय कृषि मंत्री जी ने कृपा करके एक सेन्ट्रल टीम मध्य प्रदेश में भेजी थी । उसने भी जो कैलैमिटी रिलीफ फंड है वह तुरन्त देने की अनुशंसा की है । मुझे विश्वास है इस संबंध में आप तुरन्त निर्णय लेंगे ताकि मध्य प्रदेश के लोग राहत की सांस ले सकें । मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी का राज था तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री पटवा जी के चुनाव क्षेत्र में लोग भूख और प्यास से मौत के शिकार हुए थे । वह बहुत ही दर्दनाक स्थिति थी । सरगुजा जिले की दर्दनाक स्थिति को प्रत्यक्ष प्रधान मंत्री जी ने अपनी आंखों से देखा था । मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री के क्षेत्र में इस दर्दनाक मौत को मैंने भी खुद जाकर देखा है मैं चाहूंगा इस रायलसीमा जिले के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे केन्द्रीय स्तर से कुछ सहायता राशि वहां प्रदान की जाए और साथ ही साथ जो कैलैमिटी रिलीफ फंड का पूरा का पूरा पैसा है वह मध्य प्रदेश के लोगों को तुरन्त प्रदान किया जाना चाहिए । आपकी अति कृपा होगी ।

जैसा मैंने अपनी बात प्रारम्भ में कही थी दरअसल भारत में एक प्राकृतिक अभिशाप है कि यहां के लोगों को बाढ़ और सूखे से प्रभावित होना पड़ता है । जहां प्राकृतिक देन है वहीं प्राकृतिक अभिशाप का भी हमको सामना करना पड़ता है । इसलिए हमारी तरफ से कुछ ऐसा पर्मानेंट अरेंजमेंट होना चाहिए. यद्यपि आपने क्राप कंटेनजेंसी प्लान बनाया हुआ है, जून में इसको सरकुलेट भी कर दिया था । यह अच्छी पहल थी लेकिन एक परमानेन्ट व्यवस्था हो जाए कि भारतवासियों को बाढ़ और सूखे से प्रभावित होकर किसी दर्दनाक स्थिति का सामना न करना पड़े । ऐसी व्यवस्था पर विचार करना बहुत आवश्यक है साथ ही हम लोगों को भी सदन में हर वर्ष इन दोनों स्थितियों से निपटने के लिए चर्चा की स्थिति का सामना न करना पड़े । मुझे विश्वास है आपके कृषि मंत्री के रहते ऐसी कोई व्यवस्था अवश्य होगी । धन्यवाद ।

DR. NARREDDY THULASI REDDY (Andhra Pradesh) : Hon. Vice-Chairman, Sir, I come from the Rayalaseema area of Andhra Pradesh. As Balramji correctly pointed out, drought is a common, regular and permanent feature in the Rayalaseema area of Andhra Pradesh. But, unfortunately, this year, along with Rayalaseema, some parts of Telangana and some parts of the coastal districts are also affected by drought. In my area, people compare floods with a cholera patient and drought with a T. B. patient. For cholera patients, the symptomes are immediately, clearly, visible and so, the members of the family of the patients take immediate care and the patients will be cured ultimately. But with regard to tuberculosis, T. B., the symptoms are not immediately visible. So, nobody takes care. Ultimately the patient succumbs. In the same way, with regard to floods, the effects are immediate and the symptoms appear severe. So, the State Governments and the Central Government take immediate care and some relief is given to the flood-affected areas. But with regard to drought, the effects are not immediate and the effects are not clearly visible. So, the State Governments as well as the Central Government are not taking proper interest in the drought affected areas. So, ultimately, mortality and loss are more in the drought-affected areas compared to flood-affected areas. This is happening.

Sir, in Andhra Pradesh, this year, almost three-fourths of the State is reeling under severe drought conditions. According to the Government report, the loss of crops is to the tune of about Rs. 520 crores and the loss of man-days is about Rs. 256 crores. In some places, this is the successive third year. So, some farmers have committed suicide. There are starvation deaths. There is migration of labour. Moreover, the drinking water problem has assumed serious proportions. Especially in the twin-cities of Hyderabad and Secunderabad, the problem is very severe. The ground-water level has gone down and thirty per cent of the bore-wells have dried up. A Central Committee visited the areas in the month of June. But, so far, no relief is

given. Some districts are declared as drought-affected districts but no help has been given. The re-scheduling of loan is not done; the fresh crop loans are not given and no help is given to the drought-affected farmers. Sir, my suggestions are; Firstly, the Government should give priority to the irrigation projects which are from the drought-affected areas while giving clearance to the irrigation projects. These projects are all over the country but the Government should give priority to those projects which are coming from the drought-affected areas and the Government should allocate more funds to complete those projects. That is number one.

Secondly, in drought-prone areas, the Government should give more importance to the minor irrigation.

Thirdly, in the drought-prone areas, the major problem is the going down of the ground water and as Jaipal Reddy Ji pointed out, the non-judicious exploitation of the ground water. There must be recharging of the ground water and at the same time there should be judicious use of ground water. Necessary steps should be taken in these two directions.

Then, Sir, recently, this aspect of artificial rain is coming up. I would like to stress more on this point. Recently in the Chevella area of Rangareddy district of Andhra Pradesh, the experiment on artificial rain was conducted and to some extent, it was successful. In the past also, these experiments were conducted in Maharashtra, in Kutch area of Gujarat and in the catchment areas of Vaitarna reservoir which is supplying drinking water to Bombay. Twelve times experiments were conducted and eleven times the experiments proved to be successful. Previously also, since 1949, the investigations are going on with regard to artificial rain in Israel, in Russia, in England and in USA. Most of the time the experiments proved to be successful. There are two methods here. One is dry method and the other is wet method. Recently in Andhra Pradesh the wet method was experimented, that is, silver iodised experiment, and it proved to be successful. In some countries, the dry method is experimented. In this method, soap powder and salt is sprinkled in the clouds through aeroplane. That was done and that was also successful to some extent. Moreover, the cost is negligible. In wet method, that is, silver iodised method, for thousand litres of water, the cost is only one paisa. With regard to dry method, for 1600 square kms within a span of three months, the cost will be Rs. 30 lakhs. So when we see the statistics, it seems that artificial rain will be a boon to the drought affected areas. My request is, a separate department should be constituted for artificial rain and funds should be allocated for this purpose separately. The scientists should be appointed and asked to make experiments on this point. I would request the Minister to give maximum importance to the artificial rain. Secondly, in drought prone areas, drip irrigation and irrigation by sprinklers is most feasible. But in our country there is no awareness regarding drip irrigation and sprinkler system in the drought prone areas among the farmers. So the Government should take steps with regard to drip irrigation and sprinklers and should provide subsidies and maximum financial assistance to the farmers for using this technique. These are some of my suggestions. One is artificial rain; the second is drip irrigation and the third is recharging of the ground water and judicious use of ground water. These are my suggestions. Thank you.

SHRI V. GOPALSAMY: Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you very much for the opportunity. Sir, agriculture is a gamble of the monsoon. The statement has revealed about a forecast made by the Indian meteorological Department... and also the rainfall which the country has received between June 1 and July 28. Sir, the Parliament is answerable to the people. And if the facts are not submitted to the Parliament, I am not to blame here the hon. Minister. On this occasion I would like to level the charges against the officials who prepare such statements. What has been stated in this statement is nothing but untruth. According to the statement, during the period June 1—July 28 of this year the cumulative rainfall was excess or normal in 28 out of 35 meteorological subdivisions and 70 per cent of the districts in the country and the rainfall was deficient in the remaining 7 meteorological subdivisions of Andaman & Nicobar Islands, Bihar plains, plains of West Uttar Pradesh, East Madhya Pradesh, Saurashtra, Kutch, Marathwada and Coastal Andhra Pradesh. Sir, in this statement there is no mention about the deficiency of rainfall in my State, Tamil Nadu. I may not be aware how much rainfall other States have received. Regarding the particulars given in the statement, I have no idea but as far as my State is concerned, the rainfall is very much deficient as compared to the previous year. But this statement says that between June 1 and July 28 only these are areas where

the rainfall was deficient. Therefore, I said this statement is nothing but untruth. So, when the facts are given to the Parliament we are bluffing the people, we are bluffing the system. Sir, many districts of my State are reeling under a severe drought and the farmers are suffering. I would like to particularly point out to the hon. Minister that some districts in my State are facing a severe drought and the farmers are the worst affected lot. Sir, already the farmers who have brought credit to the country through cultivation and production of food, are under the spell of loans and debts. The loans and debts have become a quagmire, a quicksand for the farmers. They are not able to come out of it. Generation after generation this burden is on their heads. Our hon. Minister would agree with me that because of the constant World Bank loan already the farmers are suffering and the Government has increased the prices of the fertilisers. Of course, you have reduced the price by a pittance. The last straw on the camel's back was put. The backbone of the camel was broken. Then you tried to show before the eyes of the camel that this straw has been taken off the load. This is what you have done as far as the prices of the fertilisers are concerned. Because we have submitted or subjugated at the feet of the World Bank, the International Monetary Fund and organisations like that and on the part of the State Government they have increased the land prices by 3½ times, the farmers cannot bear the burden.

Sir, from this statement I find that Maharashtra has informed, Uttar Pradesh has informed, Madhya Pradesh has informed, Andhra Pradesh has reported, Karnataka has reported but there is no mention about the reporting of the State Government of Tamil Nadu. It means that the State Government has not sent a report. I feel very sad. I come from a State where the State Government has miserably failed in its duty. That means if the report has not reached the Central Government about the drought conditions of my State, then it is a pity. I am very sad that the State Government has failed in its duty. The problem of drinking water is very acute in the capital of my State, Madras, and also in many parts of the State. In Madras city the people have to suffer in the scorching sun to fetch a pot of drinking water. They are in queues for water. The drinking water problem would have been solved if the Veeranam project had been implemented when Dr. Kalaigner was the Chief Minister of the State. But for political reasons that project was criticised and false charges were framed. Now, finally, the present Chief Minister also says that the Veeranam project is a very good project and it should be implemented. Now the people know what the reasons are. We started the Veeranam project to solve the problem of drinking water in Madras city. Dr. Anna, when he was the Chief Minister, thought of the Veeranam project. Now the Telugu-Ganga project is also hanging. The State Government must also be held responsible for the delay. So, the problem is there. Even the Congress party people started agitation not only in Vellore but also in Madras breaking the pots to show the public how much the people are suffering. But there is no mention about the drought conditions of my State. In the villages people have to walk miles to get a pot of water.

Sir, after 46 years of independence the people in the country are not able to get drinking water. This is the country that we have created after independence. In the villages the people are downtrodden, the toiling masses, who work hard from dawn to dusk. Their family members, their mothers and their sisters have to walk miles to fetch a pot of drinking water. This is the condition that we have created. But there is no mention about the drinking water problem of my State. Of course, we have established the TWAD Board to solve the problem. The people are suffering. Water-borne diseases have spread throughout the State. Many of the deaths which occurred due to cholera have not been reported in the hospitals. Many deaths have occurred due to cholera and other serious diseases. This is the condition today in my State. So, the drought condition is very much there and the farmers are suffering and whatever resources they have got, they have already invested. This is the season of sowing in many parts of the State. The Cauvery delta is already suffering because of the stabbing on the back by the State of Karnataka and—Madam there may object to what I may say—the betrayal by the Central Government. The people and farmers in the Cauvery delta are suffering. This is the time for sowing operation, but there is no rain. There is no rain throughout the State. But the statement does not mention a word about the deficiency of rainfall in my State. Such a statement has been made here. What is happening? When the National Front Government was here, when we were in power, we waived the loans and the farmers were rescued from the quagmire of debts. Now in the month of June coercive action was taken by the State Government against the farmers throughout the State. Properties were attached in the name of collection of dues. This

is the condition in my State. So, they are the worst affected. To add insult to injury, there is no mention about the drought conditions of my State of Tamil Nadu. I would like to know whether the State of Tamil Nadu exists in the map of India or not. If the State Government had already sent a report seeking assistance from the Central Government, then I would accuse the Central Government since nothing has been mentioned in the statement. But, I do not want to make any charge in haste. If the State Government has not sent any memorandum, if it has not sought any assistance from the Central Government, that means the State Government has betrayed the people of Tamil Nadu. The hon. Minister is here.....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Please conclude.

SHRI V. GOPALSAMY: Like the people of Bihar and other parts of the country, the farmers, the villagers, and the people of Madras are also suffering a lot due to drought conditions in that State.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Shri Mohd. Masud Khan...(*Interruptions*)

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): Sir, I just want to say something about Tamil Nadu. I want to join my friend, Mr. Gopalsamy...(*Interruptions*)

SHRI V. GOPALSAMY: Like yesterday... (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: We share your anguish...(*Interruptions*)

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Please let me finish. Sir, I think it is a tragedy. I also come from Tamil Nadu and, I think, it is very unfortunate that the hon. Minister has not referred to the really serious drought conditions and the problem of drinking water in Tamil Nadu. I would request the hon. Minister to tell us in his reply as to what the position in the State is. I also want to know if the State Government is awake or if they are all still fasting on the Marina. Have they sent any request for assistance to the Central Government? Obviously, the Minister cannot respond to it unless the State Government has sent a request. I would request the hon. Minister to tell us whether the Tamil Nadu Government had even asked for any assistance...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Mr. Gopalsamy has already mentioned about the problems of Tamil Nadu.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: I want to join him...(*Interruptions*)

SHRI V. GOPALSAMY: Mr. Vice-Chairman, Sir, I am very happy that Mrs. Jayanthi Natarajan has associated herself with my sentiments expressed yesterday and today...(*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): We will support you when you are right and not when you are on the wrong path.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Other Members also have to talk about the drought conditions in other parts of the country. You want to hijack the rights of other Members...(*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: Tamil Nadu is a drought-prone area. But there is no mention about the drought conditions prevailing in Tamil Nadu...(*Interruptions*)

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: My information is that the Central Government has not...(*Interruptions*)

SHRI S. MUTHU MANI (Tamil Nadu): Don't blame my Government. The Karnataka Government has not implemented the award ...(*Interruptions*)

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: My information is that the State Government has said that no area was affected by drought in Tamil Nadu...(*Interruptions*)

SHRI V. GOPALSAMY: It is a betrayal by the State Government against the people of Tamil Nadu...(*Interruptions*) We know that drought prevails in Tamil Nadu. It is callousness on the part of Tamil Nadu Government is not making a report...(*Interruptions*)

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: It is shameful...(*Interruptions*)

SHRI S. MUTHU MANI: The charge levelled by Mr. Gopalsamy and Mrs. Natarajan are nothing but an untruth. They are misleading the House...(*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: It is very well known that the Tamil Nadu Government is sleeping on the problems of the farmers... (*Interruptions*)

SHRI S. MUTHU MANI: It is the Central Government which is not sincere about enforcing the tribunal's award...(*Interruptions*)

SHRIMATI MIRA DAS (Orissa): Sir, the discussion should not be diverted to Tamil Nadu...*(Interruptions)*. We would also want to say something...*(Interruptions)*

SHRI V. GOPALSAMY: The problem is acute in our State and we have a right to talk about it in the House...*(Interruptions)*

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: We are concerned about our State...*(Interruptions)*

SHRIMATI MIRA DAS: We would also want to talk about our States...*(Interruptions)*

SHRI V. GOPALSAMY: You may not be concerned about our State. But we are concerned. That is why Mrs. Natarajan and myself are raising it...*(Interruptions)*

श्री मुहम्मद मसूद खान (उत्तर प्रदेश): मोहतरम, मैंने वजीरे जरायत साहब का बयान सुना और पढ़ा भी और जायसवाल साहब की तकरीर भी सुनी । उनका एक सवाल का जवाब देखा । . . . (व्यवधान) . . . आप लोग जब बोलते हैं तो मैं खामोश रहता हूं । यह कोई तरीका नहीं है । . . . *(व्यवधान)* . . .

شری محمد مسعود خان "اتر پردیش": محترم میں نے وزیر زراعت صاحب کا بیان سنا اور پڑھا بھی اور جائسوال صاحب کی تقریر بھی سنی۔ ان کے ایک سوال کا جواب دیکھا... "مداخلت"... آپ لوگ جب بولتے ہیں تو میں خاموش رہتا ہوں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے... "مداخلت"...

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN: Whenever we raise a matter relating to Tamil Nadu, everybody starts interrupting.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Mr. Venkatraman, you can go to the Lobby to discuss these matters.

श्री मुहम्मद मसूद खान: जायसवाल साहब का सवाल भी मैंने पढ़ा, जिसमें उन्होंने पूछा था कि सूखा किन-किन जिलों में पड़ा है ? तो उसका जवाब आया कि सूचना एकत्र की जा रही है । इन दोनों को सामने रखकर गालिब का एक शेर याद आ गया —

हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन
खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक ।

. . . *(व्यवधान)* . . .

तो फिर उसके बाद पढ़ देंगे —

कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक ।

मोहतरम, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, खासकर बनारस, गोरखपुर और फैजाबाद, जिसमें आजमगढ़ जिला भी है, इतना भयंकर सूखा पड़ा हुआ है कि जिन लोगों ने नर्सरी धान की लगाई थीं वह सूख गई और जिन लोगों ने थोड़ा बहुत दो-चार परसेंट धान का पौधा लगाया था वह भी सूख गया । पानी का स्टेटा बहुत नीचे चला गया है । नहर पानी दे नहीं रहा है, हैंड पंप पानी खत्म हुआ जा रहा है और बिजली की हालत यह है कि ट्रांसफोर्मर जल जाए तो रिश्वत देने के बाद भी पन्द्रह दिन के अंदर नहीं लग पाता । उसके बाद सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि आजमगढ़ का डी० एम० सो रहा है । उसने अब तक रिपोर्ट नहीं दी कि आजमगढ़ सूखा-पीड़ित है ।

मान्यवर, सबसे बड़ी चीज यह है कि आपके सामने सही रिपोर्ट आनी चाहिए । आप सिर्फ एक फैसला कर लीजिए । जुलाई माह के अंदर, पूरे जुलाई के अंदर, जिलों के अंदर या तो बाढ़ की मीटिंग हो जाती है या सूखे की मीटिंग हो जाती है, मगर पूर्वी जिला में कोई मीटिंग नहीं हुई । गवर्नर राज, मुझे माफ करेंगे, गुस्ताफी माफ कर देंगे, ऐसा मालूम होता है कि अंग्रेजों का राज भी ऐसा नहीं था । उस वक्त जो डी०एम० या दूसरे अधिकारी थे उनको कुछ तो आवाम से मोहब्बत थी, लेकिन इनको जरा भी मोहब्बत नहीं है । मेरी आपसे यह गुजारिश है कि आप किसी एक्सपर्ट को भेज दीजिए, उनसे रिपोर्ट लीजिए और अगर यह मशारिकी-हजल, जिसमें आजमगढ़ और जौनपुर आते हैं और सब-जिला आते हैं वह भयंकर सूखे की लपेट में हैं तो वहां के अधिकारियों को आप सस्पेण्ड कर दीजिए कि तुम इस लायक नहीं हो कि आवामी दौर पर तुम डी०एम० रह सको या जिलाधिकारी रह सको या एस०डी०एम० रह सको । वरना यह मुल्क तबाह हो जाएगा, लोग भूख से मर जाएंगे । आज पोजीशन यह है कि आपने जवाहर रोजगार योजना का जो पैसा दिया, वह आप यहां से बैठकर एक बार जज कर लीजिए कि वह पैसा अब तक काम में नहीं लगाया गया है । वह क्या कर रहे हैं, चाहे प्रदेश हो या जिला हो ? मैं अपनी बात कहता हूं, वहां साल भर के अंदर योजना की कोई मीटिंग नहीं हुई, बिजली विभाग की कोई मीटिंग नहीं हुई, सूखा और बाढ़ की कोई मीटिंग नहीं हुई । आखिर यह डी०एम० वगैरह या दूसरे अधिकारी क्या कर रहे हैं ? आपके अधिकारी, कर्मचारी क्या कर रहे हैं ? आवाम के साथ कोई आवामी जजबात को सामने रखकर आपको सही रिपोर्ट दे दे, बस इतना हम चाहते हैं । उसके बाद आप जो कर सकते हैं वह करें । वह नहीं कर सकते । इस वास्ते नहीं कर सकते कि किसी जिला में जाकर वहां विकास भवन देख लीजिए । तो पता चलेगा कि बहुमंजिला और एअर कंडीशण्ड बना हुआ है । जब जिनकी बिजली नहीं कटती वह बगैर बिजली के किसानों का दुख क्या जाने ? जो हमेशा ठंडक में रहते हैं, अगर बिजली किसी वजह से नहीं है तो जनरेटर है, वह क्या जाने कि कैसे किसान धूप में रहता है, कैसे किसान जाड़े में रहता है, कैसे किसान फसल बोता है ? मैं जानता हूं, एक-एक

[ ] Translation in Arabic Script.

किसान जो है वहां रो रहा है, तड़प रहा है, पोखरों में पानी नहीं है, जिसको जानवर पी सकें और किसी जगह चारा नहीं है, जिसे जानवर खा सकें । मोहतरम, मैं आपसे यह गुज़ारिश करना चाहता हूं कि आप यह बिजली की हालत देखें, पानी की हालत देखें और सबसे पहले मेरी तस्कीन हो जाएगी . . . . . .

4.09 p.m.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): We are now discussing the Calling-Attention Motion now.

श्री मोहम्मद मसूद खान : मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं । मुझको तस्कीन सिर्फ इस पर हो जाएगी और दरवाजा खुल जाएगा कि आप किसी एक्सपर्ट को भेजकर यह पता लगा लें कि यह पूर्वी जिला, जिसमें आजमगढ़ वगैरह आते हैं, वह भयंकर सूखे में है कि नहीं ? अगर सूखे में है तो आपके पास आज तक क्यों रिपोर्ट नहीं आई ? रिपोर्ट न देने वाले को आप एक बार सज़ा दे दें, आपके पास सही रिपोर्ट आएगी । मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट इसी तरह से चलाई जाती है । मैं भी सरकार में था और इसी तरह से सख्त कदम उठाता था तो सरकार चलती थी । शुक्रिया ।

ضلع بھی ہے۔ اتنا بھینکر سوکھا پڑا ہے کہ جن لوگوں نے نرسری دھان کی لگائی تھی وہ سوکھ گئی اور جن لوگوں نے تھوڑا بہت دو چار پرسینٹ دھان کا پودا لگایا تھا وہ بھی سوکھ گیا۔ پانی کا اسٹیٹا بہت نیچے چلا گیا ہے۔ نہر پانی دے نہیں رہا ہے ہیڈ پر پانی ختم ہوا جا رہا ہے اور بجلی کی حالت یہ ہے کہ ٹرانسفارمر جل جائے تو رشوت دینے کے بعد بھی پندرہ دن کے اندر نہیں لگ پاتا۔ اس کے بعد سب سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ اعظم گڑھ کا ڈی۔ ایم۔ سو رہا ہے۔ اس نے اب تک رپورٹ نہیں دی کہ اعظم گڑھ سوکھا پیڑت ہے۔

مائنور۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپکے سامنے صحیح رپورٹ آنی چاہیے۔ آپ صرف ایک فیصلہ کر لیجیے۔ جولائی ماہ کے اندر۔ پورے جولائی کے اندر ضلعوں کے اندر یا تو باڑھ کی میٹنگ ہو جاتی ہے یا سوکھے کی میٹنگ ہو جاتی ہے مگر پوربی ضلع میں کوئی میٹنگ نہیں ہوئی۔ گورنر راج۔ مجھے معاف کریں گے۔ گستاخی معاف کر دیں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انگریزوں کا راج بھی ایسا نہیں تھا۔ اس وقت جو ڈی۔ ایم۔ یا دوسرے ادھیکاری تھے ان کو کچھ تو عوام سے محبت تھی۔ لیکن ان کو ذرا بھی محبت نہیں ہے۔ میری آپ سے یہ گذارش ہے کہ آپ کسی ایکسپرٹ کو بھیج دیجیے۔ ان سے رپورٹ لیجیے اور اگر

شری محمد مسعود خان "اتر پردیش": جائسوال صاحب کا سوال بھی میں نے پڑھا جس میں انھوں نے پوچھا تھا کہ سوکھا کن کن ضلعوں میں پڑا ہے۔ تو اس کا جواب آیا کہ سوچنا ایکسرسائز کی جا رہی ہیں۔ ان دونوں کو سامنے رکھ کر غالب کا ایک شعر یاد آ گیا...

ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن
خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک

....."مداخلت"...

تو پھر اس کے بعد پڑھ دیں گے۔: کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔

محترم۔ پوربی اتر پردیش میں۔ خاص کر۔ بنارس۔ گورکھپور اور فیض آباد جس میں اعظم گڑھ

4.00 P.M.

[ ] Transliteration in Arabic Script.

[ ] Translation in Arabic Script.

وجہ سے نہیں ہے تو جزیٹر ہیں۔ وہ کیا جانیں کہ کیسے کسان دھوپ میں رہتا ہے۔ کیسے کسان جاڑے میں رہتا ہے۔ کیسے کسان فصل بوتا ہے۔ میں جانتا ہوں ایک ایک کسان جو ہے وہاں رو رہا ہے۔ تڑپ رہا ہے۔ بوکھروں میں پانی نہیں ہے۔ جس کو جانور پی سکیں۔ اور کسی جگہ چارہ نہیں ہے۔ جسے جانور کھا سکیں۔ محترم۔ میں آپ سے یہ گذارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بجلی کی حالت دیکھیں۔ پانی کی حالت دیکھیں اور سب سے پہلے میری تسکین ہو جائے گی.....

THE VICE CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): We are now discussing the Calling-Attention Motion now.

شری محمد مسعود خان: میں ایک منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ مجھ کو تسکین صرف اس پر ہو جائے گی۔ اور دروازہ کھل جائے گا۔ کہ آپ کسی ایکسپرٹ کو بھیج کر پتا لگائیں کہ یہ پوربی ضلع جس میں اعظم گڑھ وغیرہ آتے ہیں وہ بھینکر سوکھے میں ہے کہ نہیں۔ اگر سوکھے میں ہے تو آپ کے پاس آج تک کیوں رپورٹ نہیں آئی۔ رپورٹ نہ دینے والے کو آپ ایک بار سزا دے دیں۔ آپ کے پاس صحیح رپورٹ آجائے گی۔ میں جانتا ہوں کہ گورنمنٹ اسی طرح سے چلائی جاتی ہے۔ میں بھی سرکار میں تھا اور اسی طرح سے سخت قدم اٹھاتا تھا تو سرکار چلتی تھی۔ شکریہ ــ

یہ مشرقی اضلاع جس میں اعظم گڑھ اور جون پور آتے ہیں اور سب ضلع آتے ہیں وہ بھینکر سوکھے کی لپیٹ میں ہیں تو وہاں کے ادھیکاریوں کو آپ سسپینڈ کر دیجیے کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ عوامی طور پر تم ڈی۔ ایم۔ رہ سکو یا ضلع ادھیکاری رہ سکو۔ یا ایس ڈی۔ ایم۔ رہ سکو۔ ورنہ یہ ملک تباہ ہو جائے گا۔ لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ آج پوزیشن یہ ہے کہ آپ نے جواہر روزگار یوجنا کا جو پیسہ دیا وہ آپ یہاں سے بیٹھ کر ایک بار نج کر لیجیے کہ وہ پیسہ اب تک کام میں نہیں لایا گیا ہے۔ وہ کیا کر رہے ہیں۔ چاہے پردیش ہو یا ضلع ہو۔ میں اپنی بات کہتا ہوں وہاں سال بھر کے اندر یوجنا کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی۔ بجلی و بھاگ کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی۔ سوکھا اور باڑھ کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی۔ آخر یہ ڈی۔ ایم۔ وغیرہ یا دوسرے ادھیکاری کر کیا رہے ہیں۔ آپ کے ادھیکاری کر کیا رہے ہیں۔ عوام کے ساتھ کوئی عوامی جذبات کو سامنے رکھ کر آپ کو صحیح رپورٹ دے دے بس اتنا ہم چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ وہ نہیں کر سکتے۔ اس واسطے نہیں کر سکتے کہ کسی ضلع میں جا کر وہاں وکاس بھون دیکھ لیجیے تو پتہ چلے گا کہ بہو منزلہ اور ائیر کنڈیشنڈ بنا ہوا ہے۔ اب جن کی بجلی نہیں کٹتی وہ بغیر بجلی کے کسانوں کا دکھ کیا جانیں۔ جو ہمیشہ ٹھنڈک میں رہتے ہیں اگر بجلی کسی

[ ] Translation in Arabic Script only.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Already several members have spoken on the Calling-Attention Motion and some Members are yet to speak and thereafter the Minister will also reply. But, according to the List of Business, at 4.00 p.m. today, there are two statements to be made and the Ministers are here and clarifications are to be sought on one statement.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, the point is that this discussion on the drought situation will get unfocused if we do not have it uninterruptedly. I suggest that we finish this discussion within half-an-hour and then take up the other things ..... *(Interruptions)* ...

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): No, Sir ... *(Interruptions)* ...

THE VICE CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): I will take the sense of the House ... *(Interruptions)* ... We can finish this discussion and the reply by the Minister also ... *(Interruptions)* ... All right. I will take the sense of the House ... *(Interruptions)* ...

SHRI V. GOPALSAMY: You follow the agenda, Sir ..... *(Interruptions)* ...

SHRI JAGDISH TYTLER: Yes, we will follow the agenda ..... *(Interruptions)* ...

श्री सिकन्दर बख्त: सदर साहब, एजेंडे के मुताबिक चलने दीजिए।

شری سکندر بخت: صدر صاحب۔ ایجنڈے کے مطابق چلنے دیجیے۔

THE VICE CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Let me take the sense of the House. We will go by the List of Business ..... *(Interruptions)* ...

SOME HON. MEMBERS: List of Business only ..... *(Interruptions)* ...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED): Sir, we have also got two Motions for reference of Bills to Joint Committees according to the Supplementary List of Business ..... *(Interruptions)* ...

† [ ] Transliteration in Arabic Script.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Before I can ask the Ministers to make their statements according to the List of Business, there are two Motions to be moved by the Minister of State for Home Affairs according to the Supplementary List of Business. Yes, Mr. Sayeed.

MOTION FOR REFERENCE OF BILL TO JOINT COMMITTEE—THE CONSTITUTION (EIGHTIETH AMENDMENT) BILL, 1993

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED): Sir, I beg to move the following Motion:

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do join in the Joint Committee of the Houses on the Bill further to amend the Constitution of India and resolves that the following members of the Rajya Sabha, namely,:—

1. Mufti Mohd. Sayeed,
2. Shri N. E. Balaram,
3. Shri Satya Prakash Malviya,
4. Shri Sikander Bakht,
5. Shri R. K. Dhawan,
6. Shri Madan Bhatia,
7. Shri Sushilkumar Sambhajirao Shinde,
8. Shri Murlidhar Chandrakant Bhandare,
9. Shri Subramanian Swamy, and
10. Shri Mentay Padmanabham,

be nominated to serve on the said Joint Committee".

The question was proposed.

(उपसभापति महोदया पीठासीन हुईं)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश): महोदया, मंत्री महोदय ने प्रस्ताव रखा है। बिल सरक्युलेट हो चुका है, मैंने और मेरी पार्टी ने बिल को देखा है। बिल के जो उद्देश्य कहे गए हैं, उससे बिल्कुल अलग उसके अंदर प्रावधान है। अगर थोड़े में कहा जाए तो सरकार की तानाशाही को स्थापित करने वाला यह बिल है। आर्टिकल 35(2) के संशोधन का मतलब है, जितनी पार्टियां यहां बैठी हुई हैं, विरोधी दल में से किसी को भी पार्लियामेंट के एक प्रस्ताव से सरकार प्रतिबंधित कर सकती